इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण इकाइयों को मिलेगी हरसंभव सहायता

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के प्रजेंटेशन में सीएम ने दिया भरोसा

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य की जरूरतों को देखते हुए यह जरूरी है कि परंपरागत ईंधन (डीजल- पेट्रोल) चालित वाहनों के स्थान पर इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए। ऐसे में प्रदेश सरकार राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण करने वाली कंपनियों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराएगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना के लिए विभिन्न अंतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल कंपनियों ने प्रस्ताव दिए हैं।

लोकभवन में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग की ओर से बृहस्पतिवार को प्रस्तुतीकरण को देखते हुए सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग में इकाइयों के लिए अनुसंधान एवं विकास, परीक्षण तथा प्रमाणन के लिए सीड

कहा- यूपी इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति-2019 का होगा उदारीकरण

एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाए। उन्होंने प्रदेश के लैंड-लॉक्ड होने के दृष्टिगत ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को प्लांट साइट से पोर्ट तक माल पहुंचाने के लिए परिवहन लागत को युक्तिसंगत बनाने की भी जरूरत बताई। कहा, राज्य सरकार ने प्रस्तावित बल्क ड्रग/मेडिकल डिवाइस पार्क के लिए जिस तरह प्रोत्साहन दिया है उसी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों के संबंध में भी लिया जाना चाहिए। ईवी के प्रयोग के लिए लोगों को जागरूक और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सीएम ने रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में भी छूट देने पर विचार की बात कही।

मेगा निवेश को दें प्रोत्साहन

उप्र. इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग (ईवीएम) नीति- 2019 में प्रस्तावित संशोधनों पर उच्चाधिकारियों से विमर्श के बाद सीएम ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र नया सेक्टर होने से यह जरूरी है कि इस नीति का उदारीकरण करके मेगा निवेश को प्रोत्साहित किया जाए। इससे सहायक इकाइयों को बढ़ावा मिलेगा। निजी इलेक्ट्रिक वाहन पार्कों को राज्य की निजी औद्योगिक पार्क योजनांतर्गत लाभ देना चाहिए। उन्होंने चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल को तार्किक रखने के निर्देश भी दिए। सीएम ने ईवी उद्योग को प्रदेश में स्थापना पर एसजीएसटी प्रतिपूर्ति के वर्तमान नियमों के स्थान पर पूंजीगत उपादान देने की नीति की जरूरत बताई।

ई-रिक्शा की खरीद के लिए सरकार देगी प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा शहरों में प्रदूषण का कारक बन रहे डीजल टैंपो/ऑटो और पैडल रिक्शा के स्थान पर ई-रिक्शा को बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। उन्होंने निर्देश दिए कि रिक्शा डीजल ऑटो चालकों को ई-रिक्शा खरीद के लिए स्वरोजगार केंद्र अथवा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत ऋण दिलाया जाए। उन्होंने ई-रिक्शा चालकों को ट्रैफिक नियमों के पालन, वाहन चलाने के प्रशिक्षण और रूट तय करने जैसे उपायों पर भी बल दिया।

वरासत अभियान का मौके पर कराएं सत्यापन : योगी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को गांवों में वरासत अभियान की कार्यवाही का मौके पर सत्यापन करने के निर्देश दिए हैं। वे बृहस्पतिवार को लोक भवन में विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश, कहा- रैंडम आधार पर कराएं पड़ताल

उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग के अधिकारी भ्रमण के दौरान वरासत अभियान के तहत निर्विवाद उत्तराधिकार की खतौनियों में दर्ज करने की रैंडम पड़ताल करें। उन्होंने इस अभियान को तेजी से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने भीषण ठंड के मद्देनजर रैनबसेरों का सुचारु संचालन, शहरी व ग्रामीण इलाकों के प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था तथा जरूरतमंदों को कंबल वितरित करने के निर्देश भी दिए। सीएम ने दैवीय आपदाओं से होने वाली हानि को न्यूनतम करने के लिए लोगों को आपदा के समय बरती जाने वाली सावधानियों के प्रति जागरूक करने तथा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के भवन निर्माण के लिए तेजी से कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने गंगा एक्सप्रेस-वे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही तेज करने के निर्देश भी दिए।

डीएनए जांच के लिए बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस : सीएम ने कहा कि डीएनए जांच के लिए प्रदेश में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की कार्यवाही तेज करें। इससे विवेचना कार्य वैज्ञानिक ढंग से सुगम होगा। अपराध से जुड़े मामलों के संबंध में सटीक जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे न्याय दिलाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो